



2026:AHC:126954

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2948/2026

किशोर

पुनरीक्षणवादी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

प्रतिपक्षीगण

पुनरीक्षणवादीगण के अधिवक्ता: रविंद्र कुमार यादव

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7.

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका, देवरिया स्थित न्यायालय संख्या 1, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 23/2026 में दिनांक 10.04.2026 को पारित आदेश तथा देवरिया स्थित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 17.03.2026 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की गई है। यह आदेश अपराध संख्या 246/2025 के अंतर्गत, बीएनएस की धारा 74, 70(2), पाक्सो अधिनियम की धारा 5जी/6 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत, पुलिस स्टेशन गौरी बाजार, जिला देवरिया में दर्ज किया गया था।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 15 वर्ष 6 माह का किशोर था; वह 27.11.2025 से जेल में है;

(ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है।

(iii) चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं है;

(iv) डीपीओ की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(v) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;

(vi) मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;

(vii) पुनरीक्षणवादी अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में बंद रहा है;

(viii) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

(ix) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई है।

राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आपराधिक पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया। यह निवेदन किया जाता है कि रिपोर्ट की गई घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और/या प्रेरित हैं। इसके अलावा, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए यह निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जाए।

इस बात में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों के लाभों का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह मानने के लिए उचित आधार हों कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है या उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपीलीय न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 में तीन ऐसी स्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें किसी नाबालिग अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये स्थितियाँ हैं:

- (i) यदि रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है, या
- (ii) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है, या
- (iii) उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे।

इस प्रकार, यह लगभग निर्विवाद है कि घटना की तिथि पर आवेदक नाबालिग था। डीपीओ की टिप्पणियों के आलोक में, आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहराए। आवेदक की माता, उसकी रिहाई पर, अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं, यानी आवेदक की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखने का वचन देती है।

उपर्युक्त के मददेनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत देने के उद्देश्य से कानून के स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं और त्रुटिपूर्ण तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। परिणामस्वरूप, वे आदेश मान्य नहीं हो सकते। विवादित आदेशों को **रद्द किया जाता है।**

उपर्युक्त टिप्पणियों के मददेनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। उपर्युक्त प्रकरण में अपराध के लिए **पुनरीक्षणवादी एक्स (किशोर)** ब्रिद्धि चंद के पुत्र, जिसकी प्राकृतिक अभिभावक माता श्रीमती उषा है को उपरोक्त प्रकरण में अपराध के लिए, 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) अभियोक्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को धमकाएगा नहीं;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(ii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;

(iii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।/269 बीएनएसएस रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दे।

10 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।